भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 289

बुधवार, 09 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
डिजिटल कॉमर्स हेतु ओपन नेटवर्क

***289. श्री के. सुधाकरनः**
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) को आधार और यूपीआई प्लेटफार्मों की तरह सुलभ और दूरगामी बनाने की कोई ठोस योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा छोटे, गैर-तकनीक-सक्षम व्यापारियों को ओएनडीसी में शामिल होने में मदद किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ओएनडीसी पर राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों के मुकाबले स्थानीय स्तर के व्यवसायों को सक्षम बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने व्यापारियों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं और किन्हीं अन्य हितधारकों को ओएनडीसी प्लेटफार्म पर किसी भी हमले या कपटपूर्ण व्यवहार से बचाने के लिए नियम और/अथवा आदेश बनाए है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 09.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 289 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : जी, हां। सरकार की यह योजना है कि जहां तक संभव हो, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) को सुलभ बनाया जाए तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए।

सरकार का प्रयास ओएनडीसी को बढ़ावा देना है, जो अपनी तरह की पहली वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल ई-कॉमर्स को सभी तक पहुंचाना है। ओएनडीसी से समानता आएगी तथा यह बड़े और छोटे पैमाने के उद्यमों को प्रतिस्पर्धा के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, वस्तुओं और सेवाओं के कुशाल आदान-प्रदान में सहायता करेगा।

ओएनडीसी को सुलभ बनाने तथा सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- छोटे विक्रेताओं और व्यवसायों को ओएनडीसी तथा इसके लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न उद्योग संघों के साथ मिलकर देशभर में जागरूकता संबंधी कार्यशालाएं आयो जित करना।

- राज्य स्तर पर संलग्नता योजनाओं में तेजी लाने के लिए, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी नियु क्त किए गए हैं। देशभर में विभिन्न ओएनडीसी जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

- उपभोक्ताओं को ओएनडीसी, स्थानीय व्यवसायों की सहायता करने से होने वाले लाभों तथा उनके चयन से देश की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी देना।

(ख) : जी, हां। सरकार, छोटे और तकनीक का उपयोग न करने वाले व्यापारियों को सशक्त बनाने तथा ओएनडीसी के जरिए स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के महत्व को समझती है। ओएनडीसी में शामिल होने में छोटे और तकनीक का उपयोग न करने वाले व्यापारियों की सहायता करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ओएनडीसी ने छोटे विक्रेताओं और व्यवसायों को ओएनडीसी तथा इसके लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न उद्योग संघों के साथ मिलकर देशभर में 25 से अधिक जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आरएआई, पीएचडीसीसीआई, फिक्की, नैसकॉम, सीआईआई और एफएचआरएआई के सहयोग से अनेक संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

- ओएनडीसी, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने ओएनडीसी के साथ राज्य स्तरीय संलग्नता में तेजी लाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। देशभर में विभिन्न ओएनडीसी जागरूकता अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

- विक्रेताओं की पहचान करने तथा उन्हें ओएनडीसी के लाभों और विक्रेता एप्लीकेशन के जरिए इसमें शामिल होने के बारे में शिक्षित करने, विक्रेता एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए विक्रेताओं की सहायता करने और प्रारंभिक स्तर की मूलभूत सूची तैयार करने में नेटवर्क भागीदारों (एनपी) की सहायता करने हेतु ओएनडीसी ने फीट ऑन स्ट्रीट (एफओएस) कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें 90 एफओएस संसाधन शामिल हैं।

- हाल ही में, ओएनडीसी ने एक अकादमी शुरू की है जो शैक्षणिक और सूचनात्मक टेक्स्ट और वीडियो सामग्री का भंडार है। ओएनडीसी अकादमी सीखने का सुव्यवस्थित अनुभव प्रदान करेगी जिसमें ओएनडीसी नेटवर्क के प्रत्येक भागीदार को सफल ई-कॉमर्स यात्रा के संबंध में मार्गदर्शन और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां उपलब्ध होती हैं।

(ग) : सरकार, स्थानीय और राष्ट्रीय, दोनों स्तर के व्यवसायों को ओएनडीसी के योग्य बनाने का प्रस्ताव करती है जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स के लिए समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ओएनडीसी में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों सहित ई-कॉमर्स उद्योग की सभी कंपनियों के लिए संभावित लाभ शामिल होंगे।

(घ) और (ङ) : ओएनडीसी और ओएनडीसी नेटवर्क के सभी भागीदार, भारत के सभी मौजूदा लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन हैं।

*****